Drishti IAS

करेंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश

जून (संग्रह)

2023

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

उत्तर प्रदेश **3**

- सरकारी स्कूलों में युवा पर्यटन गतिविधियों हेतु दिये जाएंगे 10 हज़ार रुपए 3
- एनजीईएल और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के बीच एमओयू 3
- नोएडा-गाजियाबाद समेत उत्तर प्रदेश के 18 ज़िले बनेंगे सेफ सिटी 5
- एंटी माइन इन्फैंट्री बूट 5
- वाराणसी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का समापन 6
- वाराणसी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का समापन 6
- 'उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना' 7
- इंडिया रैंकिंग- 2023 : शीर्ष विश्वविद्यालय रैंक में बीएचयू को मिला पाँचवा स्थान 7
- मिशन नंद बाबा 9
- उत्तर प्रदेश के सभी कमिश्नरी पर खुलेगा सैनिक स्कूल, रक्षा मंत्रालय ने दी सहमति 10
- पॉवर ऑफ अटॉर्नी को लेकर योगी कैबिनेट का फैसला 11
- चंद्रावती में गंगा तट पर बनेगा पक्का घाट 12
- उत्तर प्रदेश की सिटी बसों में यात्रियों को मिलेगी 10 प्रतिशत की छूट 12
- प्रतापगढ़ और देवरिया में 8000 करोड़ रुपए से अधिक की दस राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई 13
- उत्तर प्रदेश में बनेंगे सुपर स्टेट हाईवे 14
- अलीगढ़ से पलवल तक बनेगा ग्रीन फील्ड हाईवे 15
- उत्तर प्रदेश में खुलेगा पहला हेरिटेज पार्क व रेल कोच रेस्टोरेंट 16
- प्रदेश में खुलेगी ओपन जेल 16
- गीता प्रेस, गोरखपुर को वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा 17
- उत्तर प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों में बनेंगी टेस्टिंग लैब 19
- उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में खुलासा : कानपुर में गंगा सबसे अधिक प्रदूषित 20
- उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू की एलएडीसीएस प्रणाली 21
- 'शक्ति दीदी'अभियान 22
- सी3आई ने IIT कानपुर से किया समझौता 22
- उत्तर प्रदेश के पाँच युवा कवियों को गोपाल दास नीरज स्मृति पुरस्कार 23
- प्रदेश में जल परिवहन व पर्यटन को प्रोत्साहन के लिये सोलर बोट का होगा संचालन 24
- उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कुल 23 प्रस्तावों पर लगी मुहर 25
- आईएमएस बीएचयू ने तैयार किया हर्बल एंटीबायोटिक 26
- बरेली में बनेगा कुत्तों पर शोध करने वाला देश का पहला कैनाइन सेंटर 27
- उत्तर प्रदेश के दो स्टार्ट-अप यूथ को:लैब नेशनल इनोवेशन डायलॉग 2022 में विजेता बने 28

नोट :

उत्तर प्रदेश

सरकारी स्कूलों में युवा पर्यटन गतिविधियों हेतु दिये जाएंगे 10 हज़ार रुपए

चर्चा में क्यों ?

30 मई, 2023 को उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि प्रदेश के प्रत्येक जनपद में सरकारी इंटरमीडिएट स्कूलों, राजकीय डिग्री कालेज, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय स्कूल, श्रमिक स्कूल (अटल) तथा कस्तूरबा गांधी विद्यालय आदि में पर्यटन संबंधी गतिविधियों के संचालन के लिये 10 हज़ार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि नई पर्यटन नीति-2022 में युवाओं को पर्यटन से जोड़ने तथा उनके माध्यम से पर्यटन गतिविधियाँ संचालित करने के लिये यह रणनीति बनाई गई है।
- उन्होंने बताया कि किसी शैक्षणिक संस्थान को वर्ष में एक बार ही आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। एक मंडल में एक वर्ष में अधिकतम 10 ऐसे क्लबों को संबंधित जनपद के ज़िलाधिकारी की संस्तुति पर यह धनराशि प्रदान की जाएगी।
- प्रदेश में युवा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये नेहरू युवा केंद्र संगठन, राष्ट्रीय सेवा योजना, एनसीसी, भारत स्काउट्स एंड गाइडस, युवक मंगल दल तथा महिला मंगल दल आदि संस्थाओं के सदस्यों के माध्यम से युवा पर्यटन क्लबों को गठित कर युवा पर्यटन गतिविधियों को संचालित किया जाएगा।
- युवा पर्यटन क्लबों को उत्तरदायी पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिये चिह्नित किया गया है, जिसके तहत बच्चों एवं युवाओं में शुरू से ही पर्यटन और संस्कृति की समझ विकसित करने की योजना बनाई गई है।
- इस पहल से पर्यटन के माध्यम से युवाओं में प्रदेश की सांस्कृतिक विविधिता की समझ विकसित कर भारतीय संस्कृति और विरासत को जानने के प्रति जागरूक किया जाएगा। युवा क्लब विभिन्न जनपदों के शैक्षणिक संस्थानों में यात्रा और पर्यटन के महत्त्व को भी आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे।

एनजीईएल और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के बीच एमओयू

चर्चा में क्यों ?

1 जून, 2023 को भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (यूपीआरवीयूएनएल) और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एनजीईएल) ने नवीकरणीय उर्जा पार्क और परियोजनाओं के विकास में सहयोग करने और उर्जा क्षेत्र मं बदलाव लाने के उद्देश्य से लखनऊ में एक सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये।

प्रमुख बिंदु

- एमओयू पर एनजीईएल के सीईओ मोहित भार्गव और यूपीआरवीयूएनएल के निदेशक (वित्त) निधि कुमार नारंग ने तथा प्रबंध निदेशक पी. गुरूप्रसाद ने हस्ताक्षर किये।
- एमओयू के तहत दोनों संगठन रिहंद जलाशय, अन्य जल क्षेत्रों और किसी भी उपलब्ध खाली भूमि, अयोध्या शहर के सौर उर्जाकरण के लिये समर्पित सोलर पीवी प्रोजेक्ट और जहाँ कहीं भी भूमि उपलब्ध कराई जाएगी, वहाँ नवीकरणीय उर्जा पार्कों और परियोजनाओं के विकास के लिये मिलकर काम करेंगे।

नोट :

- एनजीईएल और यूपीआरवीयूएनएल दोनों मिलकर नवीकरणीय उर्जा उत्पादन दायित्व, उत्पादन में लचीलापन और नवीकरणीय उर्जा और उर्जा भंडारण को साथ मिलाकर ताप/जल विद्युत स्टेशनों की समयसारिणी तैयार करने जैसे कार्यों को पूरा करने के लिये संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) बनाने पर काम करेंगे।
- उल्लेखनीय है कि एनटीपीसी भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी है। इसकी कुल स्थापित क्षमता (संयुक्त उद्यमों और सहयोगी कंपनियों सहित) करीब 72 गीगावाट है।
- नवीकरणीय उर्जा कारोबार को बढ़ाने के लिये एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एनजीईएल) बनाई गई जो कि नवीकरणीय उर्जा पार्क और हरित हाइड्रोजन, उर्जा भंडारण तकनीक और चौबीसों घंटे नवीकरणीय उर्जा बिजली क्षेत्र में विकास कार्य सहित तमाम परियोजनाओं पर काम करेगी।
- विदित है कि यूपीआरवीयूएनएल का गठन उत्तर प्रदेश में बिजली उत्पादन स्टेशनों को स्थापित करने और परिचालन के लिये किया गया। वर्तमान में यूपीआरवीयूएनएल के प्रदेश में 5,820 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाले चार ताप विद्युत स्टेशन हैं और एक ताप विद्युत स्टेशन 1,320 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ एनटीपीसी के साथ संयुक्त उद्यम में है।
- यूपीआरवीयूएनएल अपने बल पर सुपर क्रिटिकल टैक्नालाजी के साथ 3,300 मेगावाट क्षमता और जुटाने की प्रक्रिया में है। इसके अलावा, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ संयुक्त उद्यम के जरिये और 1,980 मेगावाट क्षमता जुटाने की तैयारी में है।
- वर्तमान में यूपीआरवीयूएनएल नवीकरणीय उर्जा और उर्जा भंडारण क्षेत्र पर भी ध्यान दे रहा है।

नोट :

नोएडा-गाजियाबाद समेत उत्तर प्रदेश के 18 ज़िले बनेंगे सेफ सिटी

चर्चा में क्यों ?

1 जून, 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में मेयर और अध्यक्षों की कार्यशाला में बताया कि राज्य सरकार महिलाओं के लिये शहरों में सुरक्षित माहौल सुनिश्चित कराने के लिये 17 नगर निगमों और गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर समेत 18 शहरों को छह महीने में सुरक्षित (सेफ सिटी) बनाएगी।

प्रमुख बिंदु

- इसके बाद एक साल के भीतर प्रदेश के सभी 75 ज़िलों के एक-एक निकाय को सेफ सिटी बनाया जाएगा।
- सेफ सिटी में ये सुविधाएँ मिलेंगी :
- सिटी बसों में कैमरे, पैनिक बटन लगेंगे।
- महिलाएँ जैसे ही पैनिक बटन दबाएंगी तो कंट्रोल रूम को तुरंत सूचना मिलेगी।
- प्रमुख चौराहों और बाज़ारों में पिंक टॉयलेट बनेंगे।
- महिला पुलिसकर्मी पिंक स्कूटी से शहर में पेट्रोलिंग करेंगी।
- स्कूल, कॉलेजों के पास ज्यादा सतर्कता होगी।
- पहले चरण के अंतर्गत गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झाँसी, फिरोजाबाद, मथुरा-वृंदावन, प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ, शाहजहाँपुर, बरेली, अलीगढ़, कानपुर, अयोध्या शामिल होंगें।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शहरों में बेहतर सुविधाएँ देने के लिये निकायों की प्रोत्साहन योजना शुरू करने का ऐलान भी किया। इसके लिये स्वच्छता, शुद्ध पेयजल, अच्छी सड़कें, सेफ सिटी और आत्मनिर्भरता जैसे पाँच मानक तय किये गए हैं।
- अपने ज़िले में प्रथम आने वाली नगर पंचायत को एक करोड़, नगर पालिका को दो करोड़ और नगर निगम को 10 करोड़ रुपए अतिरिक्त दिये जाएंगे।

एंटी माइन इन्फैंट्री बूट

चर्चा में क्यों ?

1 जून, 2023 को डीएमएसआरडीई (रक्षा सामग्री भंडार और अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान) के निदेशक डॉ. मयंक द्विवेदी ने बताया कि संस्थान के वैज्ञानिकों ने सेना की इन्फेंट्री बटालियन के लिये विशेष जूते तैयार किये हैं, जो माइंस फटने पर जवानों को सुरक्षित रखेंगे।

प्रमुख बिंदु

- विशेष प्रकार का यह जूता माइंस के प्रेशर का प्रभाव काफी कम कर देगा। इससे पैर पड़ने के बाद विस्फोट तो होगा पर बहुत अधिक नुकसान नहीं होगा।
- भारतीय सेना की इन्फेंट्री बटालियन की सबसे बड़ी चुनौती जवानों को माइंस से बचाना है। अक्सर दुश्मनों की बिछाई माइंस फटने से जवानों के पैर गंभीर रूप से जख्मी हो जाते हैं। इसके लिये सेना ने डीएमएसआरडीई के वैज्ञानिकों से मदद मांगी थी। करीब दो-तीन साल चले शोध के बाद वैज्ञानिकों ने इसे बनाने में कामयाबी हासिल की है।
- एंटी माइन इन्फेंट्री बूट कई प्रकार के हल्के सिरेमिक पोरस और एरामिड के हाइब्रिड भाग को मिलाकर बनाया गया है। इस वजह से तीन किलोग्राम वजनी होने के बावजूद जूते से दबाव नहीं पड़ता है।
- एंटी माइन इन्फेंट्री बूट का कई बार परीक्षण किया गया। एम-14 माइंस में परीक्षण के दौरान देखा गया कि इस जूते ने 160 गुना से भी अधिक दबाव कम कर दिया। इससे माइंस में विस्फोट तो हुआ, पर कोई नुकसान नहीं हुआ।

नोट :

वाराणसी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का समापन

चर्चा में क्यों ?

3 जून, 2023 को भारत की आध्यात्मिक राजधानी वाराणसी उत्तर प्रदेश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी)-बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (बीएचयू) परिसर में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स (केआईयूजी) 2022 का समापन हुआ।

प्रमुख बिंदु

- पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ (पीयूसी) को 26 स्वर्ण, 17 रजत और 26 काँस्य पदकों के साथ समग्र चैंपियन घोषित किया गया।
- गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर (जीएनड़ीयू) 24 स्वर्ण, 27 रजत, 17 काँस्य के साथ दूसरे स्थान पर और जैन विश्वविद्यालय, कर्नाटक 16 स्वर्ण, 10 रजत, 6 काँस्य पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा।
- गौरतलब है कि इस साल खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण 25 मई से 3 जून तक उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। ये प्रतियोगिताएँ वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में आयोजित की गई।
- खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स (केआईयूजी) 2022 में 200 से अधिक विश्वविद्यालयों के 4000 से अधिक एथलीटों ने 12 प्रतियोगिता दिनों में 21 खेलों में प्रतिस्पर्धा की।
- खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण के शुभंकर का नाम जीतू रखा गया था, जो उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु स्वैंप डियर (बारहसिंघा) का प्रतिनिधित्व करता है।
- उल्लेखनीय है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण वर्ष 2020 में ओडिशा में आयोजित हुआ था तथा दूसरा संस्करण वर्ष 2022 में बंगलुरू, कर्नाटक में आयोजित किया गया था (कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2021 से 2022 में स्थानांतरित)।

पैटर्न रणनीति पाठ्यक्रम संग्रह FAQS राज्य विशिष्ट जानकारी

वाराणसी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का समापन

चर्चा में क्यों ?

3 जून, 2023 को भारत की आध्यात्मिक राजधानी वाराणसी उत्तर प्रदेश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी)-बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (बीएचयू) परिसर में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स (केआईयूजी) 2022 का समापन हुआ।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ (पीयूसी) को 26 स्वर्ण, 17 रजत और 26 काँस्य पदकों के साथ समग्र चैंपियन घोषित किया गया।
- गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर (जीएनडीयू) 24 स्वर्ण, 27 रजत, 17 काँस्य के साथ दूसरे स्थान पर और जैन विश्वविद्यालय, कर्नाटक 16 स्वर्ण, 10 रजत, 6 काँस्य पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा।
- गौरतलब है कि इस साल खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण 25 मई से 3 जून तक उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। ये प्रतियोगिताएँ वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में आयोजित की गई।
- खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स (केआईयूजी) 2022 में 200 से अधिक विश्वविद्यालयों के 4000 से अधिक एथलीटों ने 12 प्रतियोगिता दिनों में 21 खेलों में प्रतिस्पर्धा की।
- खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण के शुभंकर का नाम जीतू रखा गया था, जो उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु स्वैंप डियर (बारहसिंघा) का प्रतिनिधित्व करता है।
- उल्लेखनीय है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण वर्ष 2020 में ओडिशा में आयोजित हुआ था तथा दूसरा संस्करण वर्ष 2022 में बंगलुरू, कर्नाटक में आयोजित किया गया था (कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2021 से 2022 में स्थानांतरित)।

'उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना'

चर्चा में क्यों ?

2 जून, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंचायती राज विभाग की प्रस्तावित 'उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना'का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- 'उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना'के अंतर्गत विदेश में बसे उत्तर प्रदेश के निवासी अब अपने पैतृक गाँव में अपने परिजनों, पुरखों की याद में सामुदायिक केंद्र, बारात घर और ऐसे ही अन्य निर्माण कार्य करवा सकेंगे।
- विदित है कि उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में लोग ग्रामीण परिवेश से निकलकर देश के विभिन्न शहरों व राज्यों तथा विदेश में निवासरत हैं और कार्यरत हैं। ऐसे लोग उत्तर प्रदेश के अपने पैतृक गाँव के विकास में सहयोग प्रदान करना चाहते हैं मगर पूर्व में कोई व्यवस्था न होने की वजह से वांछित सहयोग प्रदान नहीं कर पा रहे थे।
- योजना के तहत अगर कोई व्यक्ति, निजी संस्था किसी ग्राम पंचायत में विकास कार्य, अवस्थापना सुविधा का विकास और पंचायतीराज अधिनियम की धारा 15 के तहत अनुमन्य कार्य करवाना या करना चाहते हैं और कार्य की लागत का न्यूनतम 60 प्रतिशत धनराशि दान स्वरूप वहन करने के इच्छुक हैं तो राज्य सरकार शेष 40 फीसदी लागत लगाएगी।
- कार्य पूरा होने के बाद राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आकार व प्रकार शिलापट्ट सहयोग करने वाले व्यक्ति या संस्था के प्रस्ताव के अनुसार अथवा उक्त भवन या अवस्थापना सुविधा के ऊपर लगवाया जाएगा।

इंडिया रैंकिंग- 2023 : शीर्ष विश्वविद्यालय रैंक में बीएचयू को मिला पाँचवा स्थान

चर्चा में क्यों ?

5 जून, 2023 को शिक्षा एवं विदेश राज्यमंत्री डॉ. राजकुमार रंजन सिंह ने इंडिया रैंकिंग 2023 जारी की, जिसमें शीर्ष विश्वविद्यालय रैंक में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (बीएचयू) को पाँचवां स्थान जबकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को नौवाँ स्थान मिला है।

प्रमुख बिंदु

- इंडिया रैंकिंग 2023 में शीर्ष विश्वविद्यालय रैंकिंग में भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरू को पहला स्थान मिला है जबकि दिल्ली के जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय को क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान मिला है।

नोट :

- वहीं इंडिया रैंकिंग 2023 में ओवरआल रैंकिंग में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास को पहला, भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरू को दूसरा और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली को तीसरा स्थान मिला है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर को पाँचवां और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को ग्यारहवाँ स्थान मिला है।
- शिक्षा एवं विदेश राज्यमंत्री डॉ. राजकुमार रंजन सिंह द्वारा जारी इंडिया रैंकिंग 2023 वर्ष 2015 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा विभिन्न संस्थाओं की रैंकिंग संबंधी उद्देश्य के लिये तैयार किये गए राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) को लागू करती है।
- विदित है कि शिक्षा मंत्रालय ने 2015 में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) का मसौदा तैयार करने का सराहनीय कदम उठाया था, जो विभिन्न श्रेणियों और विषय क्षेत्रों में देश के उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) की गुणवत्ता एवं उत्कृष्टता का आकलन करने के लिये बहु-आयामी मापदंडों को परिभाषित करता है और उन्हें इन मापदंडों पर हासिल कुल अंकों के आधार पर रैंक प्रदान करता है।
- शिक्षा एवं विदेश राज्यमंत्री डॉ. राजकुमार रंजन सिंह ने कहा कि इंडिया रैंकिंग देश के उच्च शिक्षण संस्थानों (एचईआई) के बीच विभिन्न श्रेणियों और विषयों के मामले में विभिन्न विश्वविद्यालयों की सापेक्ष स्थिति के आधार पर उनकी पहचान करने में छात्रों के लिये एक मूल्यवान उपकरण के तौर पर काम करती है।
- इस रैंकिंग ने विश्वविद्यालयों को शिक्षण, अनुसंधान, संसाधनों और बुनियादी ढाँचे से जुड़ी सुधार की जरूरत वाले क्षेत्रों की पहचान करने में भी मदद की है।
- यह देश के उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) की इंडिया रैंकिंग का लगातार आठवाँ संस्करण है। इंडिया रैंकिंग के 2023 संस्करण में शामिल किये गए तीन विशिष्ट पहलू इस प्रकार हैं:
  - कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र नाम के एक नए विषय का समावेश
  - दो अलग-अलग एजेंसियों को एक जैसे आँकड़े प्रदान करने के विभिन्न संस्थानों के बोझ को कम करने के उद्देश्य से इंडिया रैंकिंग में अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीच्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स (एआरआईआईए) द्वारा पूर्व में निष्पादित 'इनोवेशन' रैंकिंग का एकीकरण।
  - अर्बन और टाउन प्लानिंग में पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले संस्थानों को शामिल करने हेतु 'वास्तुकला' के दायरे का 'वास्तुकला एवं नियोजन' तक विस्तार।
- नई श्रेणी (नवाचार) एवं नए विषय (कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र) और 'वास्तुकला' से 'वास्तुकला एवं नियोजन' के विस्तार के साथ, इंडिया रैंकिंग का मौजूदा पोर्टफोलियो उन 13 श्रेणियों एवं विषयों तक बढ़ गया है जिन्हें इंडिया रैंकिंग 2023 में रैंक प्रदान किया गया है।
- इंडिया रैंकिंग 2016 के प्रथम वर्ष के दौरान, विश्वविद्यालयों के साथ-साथ तीन क्षेत्र-विशिष्ट रैंकिंग यानी इंजीनियरिंग, प्रबंधन और फार्मेसी संस्थानों के लिये रैंकिंग की घोषणा की गई थी। आठ वर्षों की अवधि में, चार नई श्रेणियाँ और पाँच नए विषय जोड़े गए हैं, जो संपूर्ण सूची को पाँच श्रेणियों यानी समग्र, विश्वविद्यालय, कॉलेज, अनुसंधान संस्थान एवं नवाचार तथा आठ विषयों यानी इंजीनियरिंग, प्रबंधन, फार्मेसी, वास्तुकला एवं नियोजन, चिकित्सा, विधि, दंत चिकित्सा और कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में वर्गीकृत करते हैं।
- शिक्षा मंत्रालय द्वारा नवंबर 2015 में शुरू की गई राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) का उपयोग इस संस्करण के साथ-साथ वर्ष 2016 से लेकर 2023 तक के लिये जारी इंडिया रैंकिंग के पिछले सात संस्करणों के लिये किया गया था। एनआईआरएफ में मापदंडों की पाँच व्यापक श्रेणियों चिन्हित की गई हैं।
- इंडिया रैंकिंग 2023 की मुख्य विशेषताएँ-
  - भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास ने समग्र श्रेणी में लगातार पाँचवें वर्ष यानी 2019 से लेकर 2023 तक और इंजीनियरिंग श्रेणी में लगातार आठवें वर्ष, यानी 2016 से लेकर 2023 तक अपना पहला स्थान बनाए रखा है।
  - समग्र श्रेणी में शीर्ष 100 में 44 सीएफटीआई/सीएफयू आईएनआई, 24 राज्य विश्वविद्यालय, 13 मानद विश्वविद्यालय, 18 निजी विश्वविद्यालय, 4 कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के संस्थान और 3 प्रबंधन संस्थान शामिल हैं।
  - भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलुरु लगातार आठवें वर्ष यानी 2016 से लेकर 2023 तक विश्वविद्यालयों की श्रेणी में शीर्ष पर रहा। यह लगातार तीसरे वर्ष यानी 2021 से लेकर 2023 तक अनुसंधान संस्थानों की श्रेणी में पहले स्थान पर रहा।
  - आईआईएम अहमदाबाद लगातार चौथे वर्ष यानी 2020 से लेकर 2023 तक प्रबंधन विषय में अपना पहला स्थान बनाए हुए है। इंडिया रैंकिंग के प्रबंधन विषय में इसे 2016 से लेकर 2019 तक शीर्ष दो में स्थान दिया गया था।

नोट :

- अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली लगातार छठे वर्ष यानी 2018 से लेकर 2023 तक चिकित्सा में शीर्ष स्थान पर है।
- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, हैदराबाद पहली बार जामिया हमदर्द को दूसरे स्थान पर धकेलते हुए फार्मेसी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर आया है। जामिया हमदर्द को लगातार चार वर्षों यानी 2019 से लेकर 2022 तक पहले स्थान पर रखा गया था।
- मिरांडा हाउस ने लगातार सातवें वर्ष यानी 2017 से लेकर 2023 तक कॉलेजों की श्रेणी में पहला स्थान बनाए रखा है।
- आईआईटी रुड़की लगातार तीसरे वर्ष यानी 2021 से लेकर 2023 तक वास्तुकला (आर्किटेक्चर) विषय में पहले स्थान पर है।
- नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बंगलुरु ने लगातार छठे वर्ष यानी 2018 से लेकर 2023 तक विधि श्रेणी में अपना पहला स्थान बनाए रखा है।
- कॉलेजों की रैंकिंग में पहले 10 कॉलेजों में से दिल्ली के पाँच कॉलेजों ने अपना दबदबा बनाए रखा है।
- द सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज ने लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष स्थान हासिल किया है।
- भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर है।
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर नवाचार श्रेणी में शीर्ष स्थान पर है।

मिशन नंद बाबा

चर्चा में क्यों ?

6 जून, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के दुग्ध उत्पादक किसानों की आय बढ़ाने और दूध की बिक्री गाँव में ही सुनिश्चित करवाने के उद्देश्य से प्रदेश के पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने 'मिशन नंद बाबा' के लोगो का अनावरण किया।

प्रमुख बिंदु

- 'मिशन नंद बाबा' के तहत उत्तर प्रदेश में दूध का उत्पादन करने वाले किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास होगा। इसके लिये राज्य सरकार नंद बाबा दुग्ध मिशन पर अगले पाँच वर्षों में 1000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
- इस मिशन के तहत गाँवों में दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों द्वारा दुग्ध उत्पादकों को उनके गाँव में ही दूध की बिक्री की सुविधा मुहैया कराई जाएगी।

नोट :

- ग्रामीण क्षेत्र में दूध का व्यापार आय का एक अतिरिक्त साधन है। इस मिशन के तहत वित्त वर्ष 2023-24 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पाँच ज़िलों में पाँच डेयरी किसान उत्पादक संगठन बनाने की योजना है जिसमें महिलाओं को अहम भूमिका दी जाएगी।
- इस मिशन के तहत किसानों को उन्नत नस्ल की स्वदेशी गायों की खरीद में अनुदान के लिये सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। गायों के लिये चारा और पशु आहार बनाने वालों को भी अनुदान दिया जाएगा।
- मिशन नंद बाबा का काम ठीक से चले इसके लिये प्रदेश स्तर पर मुख्य सचिव और जनपद स्तर पर डीएम की अध्यक्षता में समितियाँ बनाई गई हैं। मिशन के जरिये सरकार पूरे प्रदेश में गाय पालने वालों का डेटाबेस भी बनाएगी।
- पशुधन और दुग्ध विकास के अपर मुख्य सचिव रजनीश दुबे कहा कि प्रदेश में डेयरी सेक्टर के अंदर नए-नए उद्योगों में निवेश की अपार संभावना है। इसके लिये सरकार ने उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति 2022 बनाई है। इस नीति का तालमेल मिशन नंद बाबा से बिठाया जाएगा।
- यह मिशन दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में 25 प्रतिशत से अधिक की वार्षिक वृद्धि लाने में सहायक होगा।

उत्तर प्रदेश के सभी कमिश्नरी पर खुलेगा सैनिक स्कूल, रक्षा मंत्रालय ने दी सहमति

चर्चा में क्यों ?

5 जून, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के सभी कमिश्नरी पर पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर सैनिक स्कूल खोले जाने के प्रस्ताव पर रक्षा मंत्रालय ने अपनी सहमति दे दी है।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि राज्य सरकार ने चार वर्ष पूर्व हर मंडल में एक सैनिक स्कूल खोलने के लिये रक्षा मंत्रालय को अनुरोध पत्र भेजा था, जिसे रक्षा मंत्रालय ने अपनी सहमति दे दी है।
- रक्षा मंत्रालय के सैनिक स्कूल सोसाइटी की ओर से राज्य सरकार को मिले पत्र के आधार पर शासन ने प्रदेश के उन सभी 16 ज़िलों के ज़िलाधिकारियों को पत्र भेजा है, जहाँ नए सैनिक स्कूल खोले जाने है।
- बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार की ओर से संबंधित ज़िलों के डीएम को भेज गए पत्र में कहा गया है कि वे अपने ज़िलों में उपयुक्त राजकीय या सहायता प्राप्त या इच्छुक निजी अथवा एनजीओ की ओर से संचालित विद्यालयों को सैनिक स्कूलों में परिवर्तित करने के लिये अनुरोध कर सकते हैं।

नोट :

- ये सभी स्कूल PPP (प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप) के आधार पर आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, आजमगढ़, बस्ती, बरेली, मुरादाबाद, बांदा, झांसी, देवीपाटन, अयोध्या, कानपुर नगर, मेरठ, सहारनपुर, मिर्जापुर तथा वाराणसी में खोले जाएंगे।
- गौरतलब है कि देश में रक्षा मंत्रालय के 25 सैनिक स्कूल हैं जबकि प्रदेश में रक्षा मंत्रालय की ओर से तीन सैनिक स्कूलों का संचालन किया जा रहा हैं जो अमेठी, झाँसी, मैनपुरी में है। इसके अलावा गोरखपुर में एक सैनिक स्कूल बनाने के लिये 90 करोड़ रुपए का प्रावधान राज्य सरकार की ओर से किया गया है। लखनऊ में यूपी सैनिक स्कूल का संचालन किया जा रहा है जो राज्य सरकार द्वारा संचालित किया जाता है।

पॉवर ऑफ अटॉर्नी को लेकर योगी कैबिनेट का फैसला

चर्चा में क्यों ?

6 जून, 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया कि राज्य में स्टांप चोरी रोकने के लिये खून के रिश्ते वाले ही मुख्तारनामे यानी पावर ऑफ अटॉर्नी को मान्य किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि पहले पॉवर ऑफ अटॉर्नी देने में महज 50 रुपए खर्च होते थे, लेकिन अब उसे रजिस्ट्री की तरह स्टांप ड्यूटी देना होगा। यानी जैसे प्रॉपर्टी होगी, वैसी ही रजिस्ट्री की फीस चुकानी होगी।
- वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि मुख्तारनामे के माध्यम से कोई व्यक्ति किसी को अपनी तरफ से या अपने काम करने के लिये अधिकृत कर सकता है।
- रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 में दी गई व्यवस्था के आधार पर मुख्तारनामे का पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य नहीं है। इसके बाद भी सामान्य जन में इसे पंजीकृत कराने की प्रवृत्ति है और हर साल इसके आधार पर पंजीकरण की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है।
- ज्ञातव्य है कि पिछले पाँच सालों में प्रदेश के रजिस्ट्री कार्यालयों में पंजीकृत मुख्तारनामे के आधार पर रजिस्ट्री कराने की संख्या 102486 है।
- इसीलिये ही राज्य सरकार ने स्टांप चोरी रोकने के लिये खून के रिश्ते वाले मुख्तारनामे को ही मान्य करने का फैसला किया है। इसके अलावा मुख्तारनामे पर रजिस्ट्री कराने वालों को पूरा स्टांप शुल्क देना होगा।
- खून के रिश्तेवालों का 5000 रुपए के स्टांप पर पंजीकरण कराया जा सकेगा। खून के रिश्तेवालों में पिता, माता, पति, पुत्र, पुत्रवधू, पुत्री, दामाद, भाई, बहन, पौत्र, पौत्री, नाती व नातिन आएंगे।

नोट :

चंद्रावती में गंगा तट पर बनेगा पक्का घाट

चर्चा में क्यों ?

7 जून, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्रालय की ओर से स्वीकृत परियोजना के तहत राज्य के वाराणसी में जैन तीर्थंकर चंद्र महाप्रभु की जन्मस्थली चंद्रावती को पर्यटन के लिहाज से विकसित किया जाएगा। यहाँ गंगा तट पर पक्के घाट का निर्माण होगा।

प्रमुख बिंदु

- यहाँ पर्यटन की सुविधाएँ बढ़ाई जाएंगी। इसके लिये शासन ने 20 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दे दी है। साथ ही पहली किस्त के तौर पर 1.50 करोड़ रुपए की स्वीकृत भी जारी कर दी है।
- जैन तीर्थंकर चंद्र महाप्रभु की जन्मस्थली चंद्रावती जैन अनुयायियों के लिये एक पवित्र स्थल है। गंगा तट पर स्थित होने के कारण यह पर्यटन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। लंबे समय से इस तीर्थ क्षेत्र में पक्के घाट के निर्माण की मांग की जा रही थी।
- चंद्रावती में पक्के घाट के निर्माण के साथ गंगा किनारे पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे।

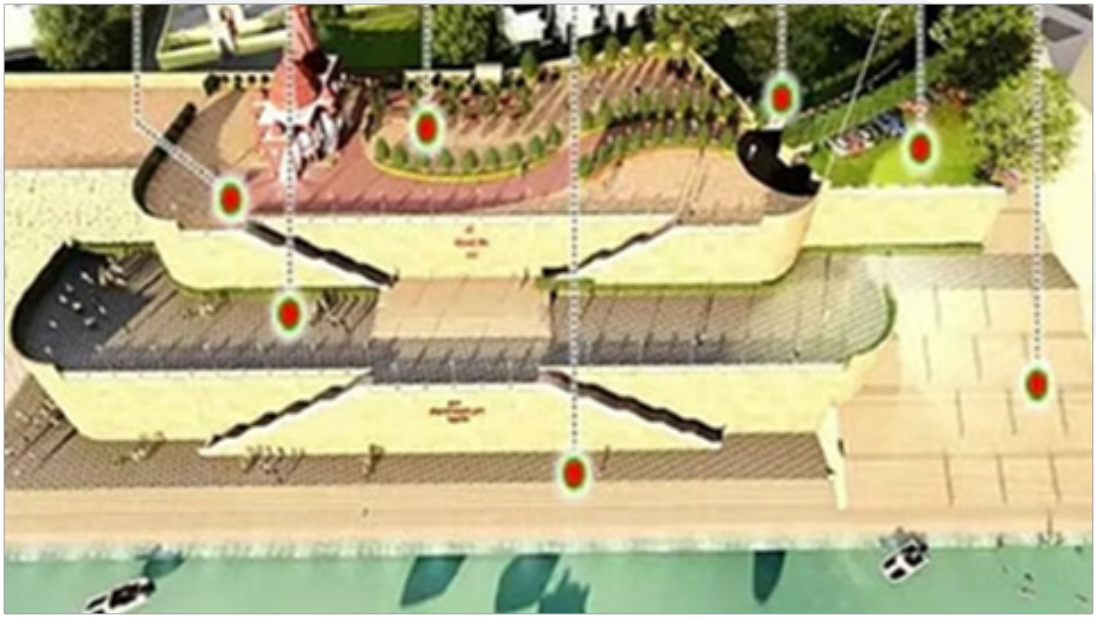

उत्तर प्रदेश की सिटी बसों में यात्रियों को मिलेगी 10 प्रतिशत की छूट

चर्चा में क्यों ?

8 जून, 2023 को उत्तर प्रदेश के नगर विकास के मुख्य सचिव अमृत अभिजात की अध्यक्षता में हुई उत्तर प्रदेश समर्पित नगरीय परिवहन निधि प्रबंध समिति की बैठक में बताया गया कि राज्य में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिये ईटीएम आपूर्तिकर्त्ता एवं एचडीएफसी द्वारा क्रियान्वित होने वाले नेशनल कामन मोबिलिटी कार्ड से किराए के भुगतान पर बसों के किराए में 10 प्रतिशत छूट मिलेगी।

प्रमुख बिंदु

- इसी तरह विभिन्न वाहनों के लिये लागू किराये में एकरूपता लाने के लिये नगरीय बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों के टिकट पर एक रुपए प्रति यात्री की समान दर से अधिभार लगाने का प्रस्ताव पास हुआ। इसके जरिये मौजूदा किराये को पूर्णांक में कर दिया गया है।
- बैठक में कन्वर्जेंस इनर्जी सर्विसेस लिमिटेड के माध्यम से 1525 वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों को जीसीसी मोड़ पर संचालित करने का प्रस्ताव मंजूर हुआ है।

नोट :

- बसों में जीपीएस, पैनिक बटन, सीसीटीवी कैमरा और महिलाओं के लिये सीट को रिजर्व किया जाएगा और प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में अनफिट, बिना परमिट, अवैध, ओवरलोड, जर्जर व डग्गामार बसों का संचालन नहीं होने दिया जाएगा। तेज गति से वाहनों के संचालन व ओवरलोडिंग के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
- जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के तहत क्रय की गई, वर्तमान में संचालित 664 बसें (सीएनजी/डीजल), लखनऊ शहर के लिये आवंटित 40 वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों के लिये वेतन, ईंधन, मोटर पार्ट्स व्यय की प्रतिपूर्ति के लिये 9953.39 लाख रुपए की मंजूरी दी गई।
- अन्य खर्चों को मिलाकर वित्तीय वर्ष 2022-23 तथा 2023-24 के लिये कुल धनराशि 25890.81 लाख रुपए का अनुमोदन किया गया।
- इसी प्रकार 300 इलेक्ट्रिक बसों को जीसीसी मोड़ पर संचालित कराने के लिये अभी तक कोई बजट नहीं है। इन बसों के संचालन पर संभावित 21.20 करोड़ वार्षिक तथा नवीन मेंटीनेंस डिपो के लिये 65.00 करोड़ रुपए का व्यय भार को अनुमोदन किया गया।
- वित्तीय वर्ष 2023-24 में 447.48 करोड़ की जररूरत होगी, इसके लिये जरूरी रकम की मांग वित्त विभाग से की जाएगी।

प्रतापगढ़ और देवरिया में 8000 करोड़ रुपए से अधिक की दस राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई

चर्चा में क्यों ?

12 जून, 2023 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में प्रतापगढ़ क्षेत्र में 2,200 करोड़ रुपए की 5 और के देवरिया में 6,215 करोड़ रुपए की 5 एनएच परियोजनाओं की आधारशिला रखी।

प्रमुख बिंदु

- केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 1290 करोड़ रुपए की लागत से प्रतापगढ़ से सुल्तानपुर तक बन रहे राष्ट्रीय राजमार्ग 330 के 43 किमी. के चौड़ीकरण से अयोध्या होते हुए प्रयागराज से प्रतापगढ़ जाने में लगने वाले समय में कमी आएगी।
- उन्होंने कहा कि राज्य के प्रतापगढ़ में 309 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित 14 किमी. बाईपास का निर्माण कार्य भी शीघ्र शुरू होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर 27 करोड़ रुपए की लागत से स्ट्रीट लाइट, बस शेल्टर आदि के लिये सड़क सुरक्षा कार्य किया जाएगा।

नोट :

- प्रतापगढ़-मुसाफिरखाना खंड के निर्माण से सीमेंट प्लांट, गैस प्लांट, बॉटलिंग प्लांट और डेयरी मिल्क फैक्ट्री उद्योगों के विकास को गति मिलेगी। इन सभी परियोजनाओं से उत्तर प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और रोज़गार के नए अवसर पैदा होंगे।
- देवरिया में 1750 करोड़ रुपए की लागत से 22 किमी. 4-लेन बाईपास का निर्माण अगस्त, 2023 में सौंपा जाएगा।
- इन परियोजनाओं से देवरिया और गोरखपुर के पिछड़े क्षेत्रों को लाभ मिलेगा तथा बिहार के साथ संपर्क भी बेहतर होगा।

उत्तर प्रदेश में बनेंगे सुपर स्टेट हाईवे

चर्चा में क्यों ?

13 जून, 2023 को उत्तर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए सुपर स्टेट हाईवे (एसएसएच) बनाए जाएंगे। इसके लिये यूपी पीडब्ल्यूडी और एनएचएआई के बीच शीघ्र ही एमओयू किये जाने की तैयारी है।

प्रमुख बिंदु

- मंत्री जितिन प्रसाद ने बताया कि वर्तमान में नई सड़कों को नेशनल हाईवे का दर्जा दिये जाने पर रोक है। इसलिये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार एसएसएच विकसित करने का फैसला किया गया है। इसके लिये केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की भी सहमति मिल चुकी है।
- ये परियोजनाएँ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की मदद से निर्मित की जाएंगी। ट्रैफिक को देखते हुए इनकी कुल चौड़ाई 4-6 लेन होगी। सुपर स्टेट हाईवे पर टोल भी लिया जाएगा।
- इससे होने वाली आय का एक हिस्सा ग्रामीण मार्गों के विकास पर खर्च होगा। यानी, इस योजना के लागू होने पर ग्रामीण सड़कों के लिये भी पर्याप्त राशि उपलब्ध हो सकेगी। इस योजना में पहले चरण में 1000-1500 किमी. स्टेट हाईवे शामिल किये जाएंगे।
- पीडब्ल्यूडी विभागाध्यक्ष को निर्देश दिये गए हैं कि वे उन स्टेट हाईवे को चिह्नित करें, जिन्हें एसएसएच का दर्जा दिया जा सकता है। ट्रैफिक के लिहाज से इन सड़कों को दो श्रेणियों में बांटा जाएगा। एक, जहाँ पीसीयू (पैसेंजर कार यूनिट) 20-30 हज़ार के बीच है और दो, जहाँ पीसीयू 30 हज़ार से ज़्यादा है।
- राज्य सरकार ज़मीन उपलब्ध कराने के साथ ही यूटिलिटी शिफ्टिंग और सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने की ज़िम्मेदारी उठाएगी। वहीं एनएचएआई इन्हें हैम (हाईब्रिड एन्युटी मॉडल) या ईपीसी (इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन) मोड में निर्माण का इंतजाम करेगा। हैम मोड में कुल लागत का 40 फीसदी एनएचएआई देता है, जबकि ईपीसी में पूरी लागत एनएचएआई ही देता है।
- निर्माण के बाद 25 साल तक यह सड़क एनएचएआई के पास ही रहेगी और उसके बाद इसे उत्तर प्रदेश सरकार के लिये हैंडओवर कर दिया जाएगा। शुरुआती 25 साल एनएचएआई टोल वसूलेगा।
- एमओयू के अनुसार, जरूरी सेवा और वित्तीय चार्ज काटने के बाद जो राशि बचेगी, उसे यूपी पीडब्ल्यूडी के खाते में जमा किया जाएगा। इस राशि का इस्तेमाल केवल राज्य की ग्रामीण सड़कों के विकास पर हो सकेगा।

नोट :

- गौरतलब है कि प्रदेश में पीडब्ल्यूडी का 276042 किमी. लंबा सड़क नेटवर्क है। इनमें 10901 किमी. स्टेट हाईवे, 6749 किमी. प्रमुख जिला मार्ग (एमडीआर), 54244 किमी. अन्य जिला मार्ग (ओडीआर) और 204148 किमी. ग्रामीण मार्ग हैं। एसएसएच व्यवस्था लागू होने से पीडब्ल्यूडी अपने संसाधनों से दो लाख किमी. से ज्यादा ग्रामीण मार्गों के लिये आवश्यक बजट का काफी हिस्से का इंतजाम कर सकेगी।

अलीगढ़ से पलवल तक बनेगा ग्रीन फील्ड हाईवे

चर्चा में क्यों ?

14 जून, 2023 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) परियोजना निदेशक पीके कौशिक ने बताया कि उत्तर प्रदेश की ताला-तालीम की नगरी अलीगढ़ को हरियाणा और एनसीआर से जोड़ने वाले अलीगढ़-पलवल हाईवे पर वाहनों का भार कम करने के साथ ही लोगों की सुविधा के लिये ग्रीन फील्ड हाईवे बनाया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि एनएचएआई स्तर पर हाईवे की डीपीआर तैयार करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अलीगढ़-पलवल हाईवे का निर्माण पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड ने कराया था। यह मार्ग 552 करोड़ रुपए की लागत से बना है।
- करीब 67 किमी. लंबे इस हाईवे के निर्माण में करीब पाँच वर्ष का समय लगा था। मार्च 2022 को पीडब्ल्यूडी ने हाईवे निर्माण का कार्य एनएचएआई को सौंप दिया था। अब एनएचएआई हाईवे की देखरेख, मरम्मत आदि का कार्य कर रहा है।
- अलीगढ़-पलवल हाईवे तीन राज्यों को आपस में जोड़ता है। इस हाईवे से दिल्ली-एनसीआर के लिये भी उत्तर प्रदेश की सीमा जुड़ती है। साथ ही, हरियाणा की सीमा भी जुड़ती है।
- इस हाईवे को तैयार करने का प्रस्ताव एनएचएआई ने वर्तमान में पीटीए मार्ग पर वाहनों की प्रतिदिन की संख्या व भविष्य में इसके सिक्स लेन होने में बाधाएँ आने की आशंका को देखते हुए किया है।
- वर्तमान में खैर-जट्टारी में बाईपास नहीं बनने से दोनों कस्बों में रोजाना घंटों लंबा जाम लगता है। फोर लेन पीटीए मार्ग पर रफ्तार भरने वाले वाहन इन दोनों कस्बों में थम जाते हैं। दोनों कस्बों में करीब 10-10 किमी. लंबा बाईपास का निर्माण होना है।
- इसके साथ ही पीटीए मार्ग के बराबर एनएचएआई ने अलीगढ़ से पलवल तक ग्रीन फील्ड हाईवे बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है। यह हाईवे सिक्स लेन होगा।

नोट :

- एनएचएआई द्वारा पीटीए मार्ग का ट्रैफिक सर्वे पूर्व में कराया जा चुका है, जिसमें 25 हज़ार वाहन प्रतिदिन गुज़रने की रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जो कि फोर लेन पर गुज़रने वाले वाहनों की संख्या से ज़्यादा है।
- पीटीए हाईवे के दोनों तरफ बसावट अधिक होने की वजह से इस मार्ग को सिक्स लेन में तब्दील किया जाना आसान नहीं है। इसके अलावा लैंड की उपलब्धता न होना भी बड़ी वजह है, जिसके चलते ग्रीन फील्ड हाईवे बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

उत्तर प्रदेश में खुलेगा पहला हेरिटेज पार्क व रेल कोच रेस्टोरेंट

चर्चा में क्यों ?

14 जून, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश का पहला रेल हेरिटेज पार्क और रेल कोच रेस्टोरेंट आगरा में खुलने वाला है।

प्रमुख बिंदु

- राज्य में आगरा कैंट स्टेशन रोड स्थित पार्क और रेस्टोरेंट में आगरा के लोगों को रेलवे के हेरिटेज की जानकारी के साथ-साथ स्वादिष्ट भोजन भी मिलेगा। जुलाई माह में शुरू होने जा रहे पार्क और रेस्टोरेंट का काम तेजी से चल रहा है।
- आगरा कैंट रेलवे स्टेशन रोड ईदगाह बस स्टैंड जाने वाले चौराहे पर रेलवे की खाली ज़मीन पर उत्तर-मध्य रेलवे और उत्तर प्रदेश का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट और हेरिटेज पार्क आकार लेने लगा है।
- विदित है कि बीते वर्ष रेलवे ने दो हज़ार वर्ग मीटर ज़मीन पर रेल कोच रेस्टोरेंट बनाने का फैसला किया था। रेस्टोरेंट के साथ हेरिटेज पार्क बनाने का फैसला बाद में लिया गया। रेल कोच रेस्टोरेंट के लिये रेल पटरी बिछाकर उस पर एक ट्रेन कोच खड़ा किया गया है।
- कोच को डिजायन करने वाले चेतन अग्रवाल ने बताया कि ट्रेन कोच को हेरिटेज व महाराजा ट्रेन जैसा लुक दिया जा रहा है। इसमें एंटिक लाइट लगाई जा रही हैं। इसमें हेरिटेज और मेरेक्कन टाइल लगाई जा रही हैं। कोच रेस्टोरेंट का प्लेटफॉर्म रेड स्टोन से बनाया जा रहा है।
- रेल कोच रेस्टोरेंट में करीब 72 लोगों के एकसाथ बैठने की व्यवस्था होगी। इसमें 36 लोग कोच के अंदर, तो 36 लोग बाहर प्लेटफॉर्म पर बैठकर लजीज व्यंजन का आनंद ले सकेंगे।
- इसके अलावा हेरिटेज पार्क में करीब 10 दुकानें होंगी। यहाँ पर भी खाने-पीने का सामान मिल सकेगा। हेरिटेज पार्क में सबसे पहले कोच रेस्टोरेंट शुरू होगा। एक टूरिस्ट गाइड कियोस्क भी होगा। टूरिस्ट को ट्रेनों के बारे में जानकारी और ऑनलाइन बुकिंग की भी सुविधा होगी। बच्चों के लिये पार्क भी बनेगा।
- आगरा रेल मंडल की पीआरओ प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि रेलवे ने ज़मीन को पाँच साल की लीज पर दिया है। इससे रेलवे को 80 लाख का राजस्व मिलेगा।
- हेरिटेज पार्क बनाने और कोच रेस्टोरेंट चलाने का टेंडर हिल्टन ग्रुप ने लिया है। रेलवे और हिल्टन ग्रुप के बीच पाँच साल तक हेरिटेज पार्क के रखरखाव और रेल कोच रेस्टोरेंट संचालित करने का करार हुआ है।
- पीआरओ ने बताया कि रेल हेरिटेज पार्क में कोच रेस्टोरेंट के साथ रेल म्यूजियम भी बनाया जाएगा। इसमें रेलवे के पुराने सिग्नल और बॉक्स टिकट व अन्य सामानों को रखा जाएगा। इसमें विजिटर्स को रेलवे के इतिहास की जानकारी मिलेगी।

प्रदेश में खुलेगी ओपन जेल

चर्चा में क्यों ?

15 जून, 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कारागार विभाग की समीक्षा के दौरान कहा कि जेलों को 'सुधार गृह' के रूप में स्थापित किया जाए। साथ ही, उन्होंने ओपन जेल की स्थापना के लिये विधिवत प्रस्ताव तैयार करने के भी निर्देश दिये।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने कहा कि ओपन जेल की स्थापना उपयोगी हो सकती है। वर्तमान में लखनऊ में एक सेमी ओपन जेल संचालित है। ओपन जेल की स्थापना के लिये विधिवत प्रस्ताव तैयार करें।

नोट :

- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेलों में मोबाइल के इस्तेमाल पर कड़ी सजा का नियम बनाने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने कुख्यात आतंकियों और शातिर अपराधियों की गहन निगरानी के लिये हाई सिक्योरिटी बैरक बनाने के निर्देश दिये हैं।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में नए प्रिजन एक्ट तैयार करके लागू किया जाए। वर्तमान में जेल अधिनियम 1894 और कैदी अधिनियम 1900 आज़ादी के पूर्व से प्रचलन में हैं। भविष्य के दृष्टिगत नया अधिनियम लागू करने की आवश्यकता है।
- उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने हाल ही में मॉडल प्रिजन अधिनियम 2023 तैयार किया है। यह कैदियों के सुधार तथा पुनर्वास की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है। इसके अनुरूप प्रदेश का नया प्रिजन एक्ट तैयार किया जाए।
- कैबिनेट ने विगत दिनों नई जेल मैन्युअल को अनुमोदित किया है। कैदियों का सुरक्षा मूल्यांकन, शिकायत निवारण, कारागार विकास बोर्ड, कैदियों के प्रति व्यवहार में बदलाव एवं महिला कैदियों व ट्रांसजेंडर आदि के लिये अलग आवास का प्रावधान जैसी व्यवस्था लागू की जाए।
- उन्होंने कहा कि जेल में अच्छे आचरण को प्रोत्साहित करने के लिये कैदियों को कानूनी सहायता, पेरोल और समय से पहले रिहाई का लाभ मिलना चाहिये। नए एक्ट में इसका प्राविधान हो।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि बंदियों के प्रवेश एवं निकास ई-प्रिजन के माध्यम से कराए जा रहे हैं। प्रिजनर्स इंफार्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम, ई-अभिरक्षा प्रमाण-पत्र, पुलिस इंटेलीजेंस सिस्टम भी लागू है। जेलों में 4200 से अधिक सीसीटीवी लगे हैं, जिनकी निगरानी मुख्यालय में स्थापित वीडियोवॉल से की जाती है। उन्होंने कहा कि ड्रोन कैमरों को वीडियोवॉल से एंटीग्रेट कर मॉनीटरिंग की जाए।

गीता प्रेस, गोरखपुर को वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा

चर्चा में क्यों ?

18 जून, 2023 को पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस, गोरखपुर को प्रदान किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में निर्णायक मंडल ने सर्वसम्मति से वर्ष 2021 के गांधी शांति पुरस्कार के लिये गीता प्रेस, गोरखपुर का चयन किया है।

नोट :

- यह पुरस्कार गीता प्रेस, गोरखपुर को अहिंसक और अन्य गांधीवादी आदर्शों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन लाने में उत्कृष्ट योगदान के लिये दिया जा रहा है।
- विदित है कि वर्ष 1923 में स्थापित गीता प्रेस विश्व में सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक है। इसने 14 भाषाओं में 41.7 करोड़ पुस्तकों का प्रकाशन किया है, जिनमें 16.21 करोड़ श्रीमदभगवद् गीता पुस्तकें शामिल हैं।
- इस संस्था ने राजस्व सृजन के लिये कभी भी अपने प्रकाशनों हेतु विज्ञापन नहीं लिये। गीता प्रेस अपने संबद्ध संगठनों के साथ जीवन के उत्तरोत्तर विकास और सर्वजन-कल्याण के लिये प्रयासरत् है।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गीता प्रेस को अपनी स्थापना के सौ वर्ष पूरे होने पर गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाना संस्थान द्वारा सामुदायिक सेवा में किये गए कार्यों की सराहना करना है।
- गांधी शांति पुरस्कार 2021, मानवता के सामूहिक उत्थान में योगदान देने के लिये गीता प्रेस के महत्त्वपूर्ण और अद्वितीय योगदान को मान्यता देता है, जो सच्चे अर्थों में गांधीवादी जीवन शैली का प्रतीक है।
- उल्लेखनीय है कि गांधी शांति पुरस्कार भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वार्षिक पुरस्कार है। वर्ष 1995 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर उनके आदर्शों के प्रति श्रद्धांजलि स्वरूप इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी।
- यह पुरस्कार राष्ट्रीयता, नस्ल, भाषा, जाति, पंथ या लिंग के भेदभाव के बगैर सभी व्यक्तियों के लिये खुला है।
- पुरस्कार में एक करोड़ रुपए की राशि, एक प्रशस्ति-पत्र, एक पटिका और एक उत्कृष्ट पारंपरिक हस्तकला/हथकरघा विशिष्ट कृति प्रदान की जाती है।
- पूर्व पुरस्कार विजेताओं में इसरो, रामकृष्ण मिशन, बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक, विवेकानंद केंद्र (कन्याकुमारी), अक्षय पात्र (बंगलूरू), एकल अभियान ट्रस्ट (भारत) और सुलभ इंटरनेशनल (नई दिल्ली) जैसे संगठन शामिल हैं।
- यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले विशिष्ट व्यक्तियों में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉ. नेल्सन मंडेला, तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. जूलियस न्येरेरे, श्रीलंका के सर्वोदय श्रमदान आंदोलन के संस्थापक अध्यक्ष डॉ. ए.टी. अरियारत्ने, जर्मनी संघीय गणराज्य के डॉ. गेरहार्ड फिशर, बाबा आमटे, आयरलैंड के डॉ. जॉन ह्यूम, चेकोस्लोवाकिया के पूर्व राष्ट्रपति वाक्लेव हवेल, दक्षिण अफ्रीका के आर्कबिशप डेसमंड टूटू, चंडी प्रसाद भट्ट और जापान के योही ससाकावा शामिल हैं।
- हाल के वर्षों में 2019 में ओमान के सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद और 2020 में बांग्लादेश के बंगबंधु शेख मुजीबुर्रहमान को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

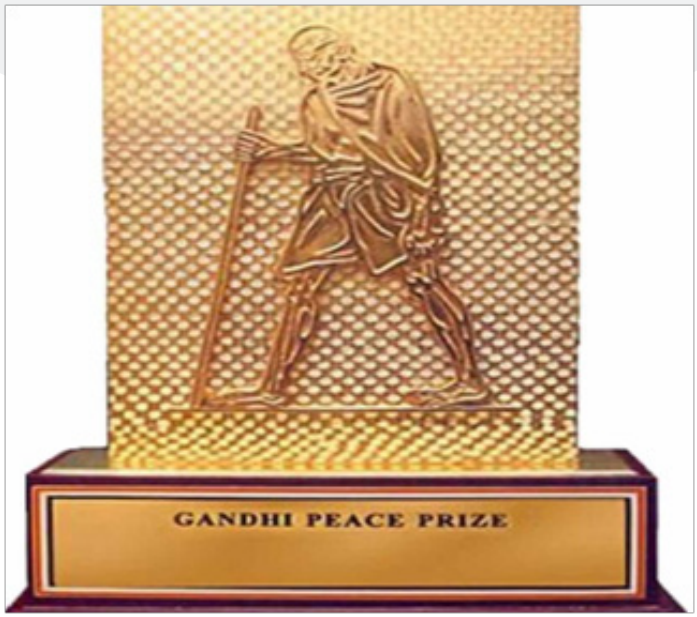

नोट :

उत्तर प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों में बनेंगी टेस्टिंग लैब

चर्चा में क्यों ?

19 जून, 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में हुई राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के संचालक मंडल की बैठक में राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों में टेस्टिंग लैब बनाने के निर्देश दिये, जिनमें जैविक व प्राकृतिक उत्पादों का सत्यापन होगा।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने कहा कि आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज (अयोध्या) में टिशू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना की जाए। यह प्रयोगशाला कम-से-कम 3 हेक्टेयर के विशाल परिसर में स्थापित हो। इसके लिये धनराशि की व्यवस्था मंडी परिषद द्वारा की जाएगी।
- उन्होंने कहा कि 'मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना' में कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बाँदा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झाँसी और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झाँसी तथा 37 अन्य महाविद्यालयों को भी इसमें शामिल किया जाएगा।
- राज्य में जैविक एवं प्राकृतिक उत्पादों के आउटलेट वर्तमान में मंडल मुख्यालय पर स्थापित हैं। इन्हें ज़िला मुख्यालय तक विस्तार देने की आवश्यकता है। मंडी समितियों में भी आउटलेट खोले जाएँ तथा जैविक व प्राकृतिक बाज़ार लगवाएँ जाने चाहिये।
- राज्य के किसानों के जैविक/प्राकृतिक उत्पादों के सत्यापन, ब्रांडिंग के लिये लैब टेस्टिंग आवश्यक है। यद्यपि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा लखनऊ, मेरठ, बनारस एवं झाँसी में प्रयोगशालाएँ संचालित हैं, लेकिन प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों में कोई लैब संचालित नहीं है। ऐसे में मंडी परिषद द्वारा प्रदेश के सभी 04 कृषि विश्वविद्यालयों में टेस्टिंग लैब स्थापित की जाएगी।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्रीय ज़रूरतो के अनुसार नए हाट पैठ और किसान मंडियों का निर्माण कराया जाना चाहिये तथा पटरी व्यवसायियों को यहाँ समायोजित किया जाना चाहिये। मंडी परिषद की सहायता से कृषि विश्वविद्यालयों में छात्रावासों का निर्माण कार्य का कृषि मंत्री द्वारा निरीक्षण किया जाएगा।

नोट :

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में खुलासा : कानपुर में गंगा सबसे अधिक प्रदूषित

चर्चा में क्यों ?

21 जून, 2023 को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गंगा, यमुना समेत प्रदेश की सभी नदियों की रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया गया है कि प्रदेश की औद्योगिक नगरी कानपुर में गंगा सबसे अधिक प्रदूषित है।

प्रमुख बिंदु

- उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में ही यह खुलासा हुआ है कि औद्योगिक नगरी कानपुर के डाउनस्ट्रीम जाना गाँव के पास गंगा में बीओडी (बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड) 4.60 मिलीग्राम प्रति लीटर है। यहीं गंगा में टोटल कोलीफॉर्म 20 हज़ार और फीकल कोलीफॉर्म 17 हज़ार पाया गया है।
- प्रयागराज के संगम क्षेत्र में गंगा का बीओडी अधिकतम 2.90 मिलीग्राम प्रति लीटर मिला है जिसे संतोषजनक माना जा सकता है।
- रिपोर्ट में गंगा से मिलने वाली वरुणा नदी का प्रदूषण खतरनाक स्तर पर बताया गया है। वाराणसी में गंगा में मिलने से पहले वरुणा का बीओडी 12.40 मिलीग्राम प्रति लीटर मिला है।
- बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार वरुणा का पानी जलीय जीवों के लिये भी काफी खतरनाक हो गया है। गंगा में मिलने से पहले वरुणा का डीओ (डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन) 3.30 मिलीग्राम प्रति लीटर है।
- यमुना आगरा से हमीरपुर तक बहुत प्रदूषित है। इटावा में यमुना का बीओडी 16.80 मिलीग्राम प्रति लीटर है, जबकि डीओ 5.80 मिलीग्राम प्रति लीटर पाया गया।
- पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बहने वाली काली नदी का पानी बेहद खतरनाक पाया गया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में बुलंदशहर में हिंडन नदी का बीओडी 54 मिलीग्राम प्रति लीटर मिला।
- नदी में डीओ शून्य मिलने से जलीय जीवों के जिंदा रहने की कोई संभावना नहीं है। मुजफ्फरनगर में नदी का यही हाल है।
- प्रदूषण के मामले में सबसे अधिक बदनाम हिंडन नदी सहारनपुर से नोएडा तक काली से अधिक प्रदूषित है। सीतापुर से बाराबंकी तक गोमती नदी का भी लगभग यही हाल है। उन्नाव और जौनपुर में सई का प्रदूषण सामान्य से अधिक पाया गया।
- नदियों के पानी में प्रदूषण का मानक

नोट :

प्रदूषण कारक	मात्रा
बीओडी	तीन मिलीग्राम प्रति लीटर अधिकतम
डीओ	पाँच मिलीग्राम प्रति लीटर न्यूनतम

- प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी आर.के. सिंह ने बताया कि नदियों की महीनेभर की गई जांच के बाद मुख्यालय रिपोर्ट जारी करता है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू की एलएडीसीएस प्रणाली

चर्चा में क्यों ?

22 जून, 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश की जनता को फ्री कानूनी सहायता देने और छोटे-छोटे विवादों को समझौते के आधार पर निपटाने के लिये उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत दो वर्ष के लिये 'कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली (एलएडीसीएस)' को लागू किया है।

प्रमुख बिंदु

- एलएडीसीएस प्रणाली में चीफ, डिप्टी एवं असिस्टेंट काउंसिल की सेवाओं के माध्यम से आम जन को कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी।
- आपराधिक मामलों में सार्वजनिक रक्षक प्रणाली की तर्ज पर आम जन को कानूनी सहायता प्रदान की जा सकेगी।
- एलएडीसीएस को लागू करने का उद्देश्य समाज के कमज़ोर और निर्बल वर्गों को प्रभावी और कुशल कानूनी सेवाएँ प्रदान करने के लिये न्यायालय आधारित कानूनी सेवाओं को मज़बूत करना है।
- यह पात्र व्यक्तियों को आपराधिक मामलों में गुणात्मक और सक्षम कानूनी सेवाएँ प्रदान करेगा।
- किसी व्यक्ति द्वारा किये जा रहे अवैध व्यापार से पीड़ित इसका सीधा लाभ ले सकेगा। इसका लाभ अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्य उठा सकते हैं।
- एलएडीसीएस का लाभ लेने के लिये पात्रता -
  - प्रदेश की पीड़ित की महिलाओं, बेटियाँ और बच्चे।
  - दृष्टिहीनता, कुष्ठ रोग, बहरेपन, दिमागी कमज़ोरी आदि निर्योग्यता से ग्रस्त व्यक्ति एवं खानाबादोश व्यक्ति।
  - सामूहिक आपदा, जातीय हिंसा, वर्गीय अत्याचार, बाढ़, अकाल, भूकंप अथवा औद्योगिक आपदा से पीड़ित व्यक्ति।

नोट :

- औद्योगिक कामगार।
- किशोर अपचारी अर्थात् 18 वर्ष तक की आयु के बालक।
- अभिरक्षा में निरुद्ध व्यक्ति।
- सुरक्षा गृह, मानसिक अस्पताल अथवा नर्सिंग होम में भर्ती मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति।
- ऐसा व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय 3,00,000 रुपए से कम हो।

'शक्ति दीदी'अभियान

चर्चा में क्यों ?

22 जून, 2023 को गौतमबुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में महिला सुरक्षा को लेकर मिशन शक्ति के तहत 'शक्ति दीदी'अभियान की शुरुआत की गई है।

प्रमुख बिंदु

- महिलाओं के साथ होने वाले अपराध में कमी लाने के उद्देश्य से 'शक्ति दीदी'अभियान शुरू किया गया है।
- विदित है कि हाईराइज सोसाइटी में रहने वाली महिलाएँ कई बार प्रदेश सरकार की योजना से वंचित रह जाती हैं। महिलाओं को मिलने वाली सरकारी योजनाओं का लाभ भी महिलाओं को 'शक्ति दीदी'के तहत दिलाया जाएगा।
- मिशन शक्ति के तहत 'शक्ति दीदी'अभियान शुरु किया गया है, जिसमें शहर, गाँव, सोसाइटी सभी वर्ग की महिलाओं को जोड़ा जाएगा।

सी3आई ने IIT कानपुर से किया समझौता

चर्चा में क्यों ?

25 जून, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित आईआईटी की हाईटेक साइबर सुरक्षा लैब सी3आई हब ने तेलंगाना पुलिस से साइबर अपराध करने वाले अपराधियों को पकड़ने से लेकर उसे सजा दिलाने तक में मदद करने का समझौता किया है।

प्रमुख बिंदु

- कानपुर स्थित आईआईटी ने आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस आधारित ऐसा टूल्स बनाया है, जो न सिर्फ अपराधियों को पकड़ने का जरिया बनेगा, बल्कि उन्हें दोषी ठहराने तक में पुलिस का मार्गदर्शन करेगा। सबसे पहले इस तकनीक का लाभ तेलंगाना को मिलेगा।
- आईआईटी देश को साइबर अटैक से सुरक्षित करने के लिये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिक लगातार नई तकनीक पर आधारित सिस्टम या टूल्स विकसित कर रहे हैं।
- सी3आई हब के प्रोजेक्ट मैनेजर प्रो. मणींद्र अग्रवाल की देखरेख में तेलंगाना पुलिस के लिये विशेष एआई आधारित सिस्टम (टूल्स) विकसित किये गए हैं।
- इस सिस्टम के पास साइबर अपराधों के सभी पैटर्न का डेटाबेस है, जिसके आधार पर वह ऑटोमेटिक अपराध को अलग-अलग वर्ग में बांट देगा।
- साथ ही अगर इस तरह का अपराध पूर्व में हुआ है तो उसकी पूरी जानकारी और अपराध करने वाले अपराधी की पूरी डिटेल बता देगा। इससे पुलिस को पूछताछ या छानबीन में आसानी होगी। साथ ही पुलिस को आवश्यक सुझाव भी देगा।
- यह सिस्टम वर्तमान अपराध और पुराने रिकॉर्ड के आधार पर पूरा एनालिसिस कर रिपोर्ट देगा। टूल्स की मदद से साइबर अपराध को काफी हद तक रोका जा सकेगा। जल्द ही अन्य प्रदेशों के साथ भी इस तकनीक को साझा किया जाएगा।
- ऐसे होते हैं साइबर क्राइम -
  - सोशल मीडिया हैक कर आपत्तिजनक मैसेज भेजना।
  - बैंक खाता हैक कर रकम निकाल लेना।

नोट :

- ईमेल आईडी हैक कर रुपए मांगना या आपत्तिजनक संदेश भेजना।
- व्हाट्सएप या फेसबुक हैकर द्वारा रुपए मांगना।
- डेटाबेस चोरी करने के लिये अकाउंट हैक करना।
- आधारकार्ड हैक कर रुपए निकालना।

उत्तर प्रदेश के पाँच युवा कवियों को गोपाल दास नीरज स्मृति पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

26 जून, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान ने प्रदेश के पाँच युवा कवियों को गोपाल दास नीरज स्मृति पुरस्कार दिये जाने की घोषणा की है।

प्रमुख बिंदु

- पुरस्कृत होने वाल कवियों में राजधानी लखनऊ के व्यंग्यकार-कवि पंकज प्रसून व युवा कवयित्री निशा सिंह, प्रयागराज के डॉ. प्रभांशु कुमार, फिरोजाबाद के कृष्ण कुमार कनक और बहराइच के वेद मित्र शुक्ला शामिल हैं।
- इन सभी कवियों को उनकी रचनाओं के लिये एक-एक लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा।
- 4 जनवरी, 1925 को उत्तर प्रदेश के इटावा में जन्मे विख्यात कवि एवं गीतकार पद्मभूषण गोपाल दास 'नीरज'की शैली समझने में आसान और उच्च गुणवत्ता वाली रही है। उन्होंने एसडी बर्मन द्वारा कंपोज किये गए और राजकपूर, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना जैसे नायकों पर फिल्माए गए कई सदाबहार गीत भी लिखे हैं।
- जन समाज की दृष्टि में वे मानव प्रेम के अन्यतम गायक थे। उन्होंने अपनी मर्मस्पर्शी काव्यानुभूति और सरल भाषा द्वारा हिन्दी कविता को एक नया मोड़ दिया है।
- विदित है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने वर्ष 2018 में गोपाल दास 'नीरज'के निधन पर उनकी स्मृति में हर वर्ष पाँच नवोदित कवियों को एक-एक लाख रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की थी।

नोट :

- गोपाल दास 'नीरज'स्मृति पुरस्कार के लिये चयनित कवि एवं उनकी रचनाएँ-
  - पंकज प्रसून - तब गीतों ने साथ निभाया।
  - निशा सिंह नवल - मैं निशा हूँ।
  - डॉ. प्रभांशु कुमार - डॉ. प्रभांशु की कलम से काव्य संग्रह।
  - कृष्ण कुमार कनक - उलझाता छविजाल तुम्हारा।
  - वेद मित्र शुक्ला - एक समंदर गहरा भीतर।

प्रदेश में जल परिवहन व पर्यटन को प्रोत्साहन के लिये सोलर बोट का होगा संचालन

चर्चा में क्यों ?

27 जून, 2023 को उ.प्र. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण तथा उ.प्र. राज्य पर्यटन विकास लि. के बीच सौर ऊर्जा चालित नौकाओं के संचालन के लिये करार हस्ताक्षरित किया गया, जिसके तहत प्रदेश में जल परिवहन व पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिये नदियों, सरोवरों व झीलों में सौर ऊर्जा चालित नौकाओं (सोलर बोट) का संचालन किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- विभिन्न नगर निगमों में 17 स्थलों पर स्थित नदियों व सरोवरों में सोलर बोट संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
- पहले चरण में यह अयोध्या, काशी, मथुरा सहित पाँच धार्मिक स्थलों पर चलेंगी। इसकी शुरुआत अयोध्या से होगी। इस तरह का प्रयोग करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है।
- धर्मनगरी अयोध्या के सरयू नदी में अत्याधुनिक 30 सोलर बोट का संचालन शुरू किया जाएगा। बोट से श्रद्धालु सरयू नदी का दर्शन पूजन कर सकेंगे साथ ही इससे जल पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। करीब एक करोड़ रुपए की लागत वाली इस बोट पर एक साथ 12 से 15 लोग बैठ सकेंगे।
- अयोध्या के बाद काशी, मथुरा, प्रयागराज और गढ़मुक्तेश्वर में सोलर बोट शुरू की जाएगी। इसके बाद अगले सत्र में चित्रकूट, आगरा, गोरखपुर, जौनपुर सहित अन्य नदी के किनारे वाले शहरों में यह सुविधा दी जाएगी।
- प्रारंभ में यूपी नेडा द्वारा सोलर बोट को आपूर्तिकर्त्ता फर्म के माध्यम से छह महीने के लिये प्रयोग के तौर पर संचालित कराया जाएगा। इसके बाद पर्यटन विकास निगम द्वारा निजी उद्यमियों के माध्यम से अनुभवी संस्था का चयन करते हुए सोलर बोट का नियमित संचालन किया जाएगा।

नोट :

उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कुल 23 प्रस्तावों पर लगी मुहर

चर्चा में क्यों ?

28 जून, 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राजधानी लखनऊ स्थित लोकभवन में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य की नई टाउनशिप स्थापना नीति के संबंध में प्रस्ताव को पास करने के साथ- साथ कुल 23 प्रस्तावों पर मुहर लगी।

प्रमुख बिंदु

- बैठक में उत्तर प्रदेश निजी विश्विद्यालय अधिनियम-2019 के तहत अयोध्या में महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये मुहर लग गई है।
- बैठक में अन्य महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव, जिन पर मुहर लगी है-
  - छोटे शहरों में निजी क्षेत्र के सहयोग से छोटी-छोटी कालोनियाँ लाई जाएंगी।
  - 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस मनाए जाने का प्रस्ताव।
  - महात्मा बुद्ध कृषि एवं कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर का प्रस्ताव।
  - जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट को उत्तर प्रदेश जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग राज्य विश्वविद्यालय करने का प्रस्ताव। कुलपति जगद्गुरु रामभद्राचार्य आजीवन कुलाधिपति रहेंगे तथा उनके बाद राज्यपाल कुलाधिपति होंगे।
  - 6 जनपदों में वायबिलिटी कैप फंड के आधार पर स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंध में प्रस्ताव।
  - जनपद कौशांबी में इंट्रो इस्राइल एक्सीलेंस ऑफ फूड के स्थापना के लिये भूमि स्थानांतरण का प्रस्ताव।
  - मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा का प्रस्ताव। इसके तहत 5 लाख तक की वित्तीय सेवा प्राप्त हो सकेगी। इसके लिये 18 से 60 साल के उद्यमी आवेदन कर सकते हैं।
  - आगरा और मथुरा में हेलीकॉप्टर सेवा का प्रस्ताव।
  - मथुरा चीनी मील का पुन: चलाए जाने का प्रस्ताव।
  - वृक्षारोपण अभियान 2023 में प्रदेश में 35 करोड़ वृक्षारोपण किये जाने का प्रस्ताव।

नोट :

आईएमएस बीएचयू ने तैयार किया हर्बल एंटीबायोटिक

चर्चा में क्यों ?

28 जून, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के बनारस स्थित बीएचयू के आईएमएस के आयुर्वेद संकाय ने गंभीर संक्रमण में रक्षा के लिये बेअसर रही एंटीबायोटिक के स्थान पर हर्बल एंटीबायोटिक तैयार की है।

प्रमुख बिंदु

- बीएचयू के आयुर्वेद संकाय के रसशास्त्र और भैषज्यकल्पना विभाग में प्रो. आनंद चौधरी के साथ डॉ. प्रिया मोहन के नेतृत्व में पूरी टीम ने हर्बल एंटीबायोटिक तैयार की है।
- माइक्रो बायोलॉजी विभाग के लैब में जीवाणु पर इसका ट्रायल किया जा चुका है। 'ग्राम निगेटिव'जीवाणु पर यह ज्यादा असरदार रहा है। इसके बाद दो चरण का अभी ट्रायल बाकी है। अगर इसमें कामयाबी मिलती है तो पूरी दुनिया के लिये हर्बल एंटीबायोटिक संजीवनी साबित होगी।
- बीएचयू के माइक्रोबायोलाजी लैब में दो तरह के जीवाणु को इसमें लिया गया है। ग्राम पॉजिटिव (मोटी कोशिका) और ग्राम निगेटिव (पतली कोशिका) पर इसका अलग-अलग असर देखा गया। वैज्ञानिकों ने पाया कि ग्राम निगेटिव पर ज्यादा असर हुआ।
- दरसअल ग्राम-निगेटिव बैक्टीरिया एंटीबॉडी के प्रति अधिक प्रतिरोधी होते हैं। हर्बल औषधियों के इस पर असर होने से बड़ी उम्मीद जगी है।
- विदित है कि चांदी के सिलोरेक को एंटीबायोटिक माना जाता है। हर्बल एंटीबायोटिक में चांदी के भस्म के अलावा नीम, वट, गिलोय, कृष्ण तुलसी हैं।
- प्रो. आनंद चौधरी ने बताया कि अभी इसमें दो चरण में काम किया जाएगा। उम्मीद है कि एक साल में इसको फाइनल टचअप दिया जा सकेगा। इसके बाद पेटेंट के लिये पेटेंट फैसिलिटिंग सेंटर (पीएफसी) को भेजा जाएगा।
- वरिष्ठ फिजिशियन डॉ. मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि साँस नली से जुड़े इन्फेक्शन, सर्दी-जुकाम, गले में खराश, साइनस, निमोनिया के साथ ही कान, छाती दर्द की समस्या होने पर लोग खुद से इलाज शुरू कर देते हैं। लोग मेडिकल स्टोर से एंटीबायोटिक गोलियाँ लेकर निगल लेते हैं। वे यह नहीं जानते कि उनकी तबीयत वायरस की वजह से खराब हुई है, जो अपना समय लेकर ही ठीक होगी।
- वायरल इँफेक्शन में एंटीबायोटिक्स खाने पर यह दवा 'जहर'का काम करती है। शरीर में इँफेक्शन से लड़ने वाले गुड बैक्टीरिया को भी नष्ट कर देती है। इससे खतरनाक बैक्टीरिया को शरीर पर हावी होने का मौका मिल जाता है। साथ ही, बैड बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स से बचने के लिये तैयार हो जाता है। फिर उस पर दवाओं का असर नहीं होता।
- आईएमएस बीएचयू के मेडिसिन विभाग के प्रो. धीरज किशोर के अनुसार बैक्टीरियल इंफेक्शन के इलाज में एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग किया जाता है। एंटीबायोटिक दो शब्दों 'एंटी'और 'बायोस'से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है 'एंटी लाइफ।
- यानी ये दवाएँ बैक्टीरिया को नष्ट कर, उन्हें बढ़ने से रोकती हैं, लेकिन हर बीमारी की वजह बैक्टीरिया नहीं होते। ऐसे में लोग बीमार होने पर खुद से दवा लेते हैं। और ग्रामीण इलाके में झोलाछाप भी वायरल इंफेक्शन में एंटीबायोटिक दे देते हैं, जो कि पूरी तरह गलत है।
- कुछ महत्त्वपूर्ण जानकारी-
  - मेडिकल जर्नल 'द लैंसेट'के अनुसार, 2019 में एंटीबायोटिक का असर कम होने से दुनिया में 12.70 लाख मौतें हुईं।
  - विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वैश्विक स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और विकास के लिये सबसे बड़े खतरों में से एक है।
  - विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार निमोनिया, टीबी और साल्मोनेलोसिस जैसे संक्रमणों की बढ़ती संख्या का इलाज करना कठिन होता जा रहा है क्योंकि उनके इलाज के लिये इस्तेमाल की जाने वाली एंटीबायोटिक कम प्रभावी हो जाती है।
  - भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के वरिष्ठ वैज्ञानिक ने दावा किया है कि भारत में इसमें सुधार के लिये जल्द ही कदम नहीं उठाए गए तो एंटी माइक्रोबियल रजिस्टेंस निकट भविष्य में एक महामारी का रूप ले सकता है। हर साल पाँच से 10 प्रतिशत की दर से यह रेजिस्टेंस बढ़ रहा है।

नोट :

बरेली में बनेगा कुत्तों पर शोध करने वाला देश का पहला कैनाइन सेंटर

चर्चा में क्यों ?

26 जून, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के बरेली के आईवीआरआई में कुत्तों के व्यवहार और उनसे संबंधित विभिन्न बीमारियों पर अध्ययन करने के लिये जल्द ही देश का पहला कैनाइन सेंटर बनाया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), दिल्ली ने इस एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर कैनाइन प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है।
- विदित है कि बरेली सहित देश के विभिन्न हिस्सों में अक्सर कुत्तों के काटने की खबर आती है। जाने-अनजाने में कई बार पालतू कुत्ते अपने मालिक पर ही आक्रामक हो जाते हैं। ऐसे में कुत्तों पर एक शोध केंद्र की आवश्यकता महसूस की गई, जिसमें उनके व्यवहार एवं बीमारियों पर शोध किया जा सके।
- आईवीआरआई बरेली ने एक डीपीआर बनाकर आईसीएआर दिल्ली को भेजा, जिसे मंजूरी मिल गई है। अगले दो महीने में आईवीआरआई बरेली में इस प्रोजेक्ट के लिये भवन निर्माण और अन्य कार्य शुरू हो जाएंगे।
- आईवीआरआई बरेली के रेफरल पॉली क्लीनिक के प्रभारी डॉ. अमर पाल ने बताया कि कैनाइन सेंटर में कुत्तों की आंतरिक और बाह्य संरचना पर विस्तृत शोध किया जाएगा। साथ ही, कुत्तों में कैंसर जैसी बीमारियों पर भी शोध होगा।
- कैनाइन सेंटर में सीटी स्कैन, एमआरआई, ट्यूमर, रेडियोथेरेपी, हाईटेक पैथोलॉजी आदि की सुविधाएँ होंगी। सेंटर का मुख्य केंद्र आईवीआरआई होगा और इसके तीन सब-सेंटर भी बनाए जाएंगे।
- आईवीआरआई बरेली के डायरेक्टर डॉ. त्रिवेणी दत्त ने बताया कि यह सेंटर सभी सुविधाओं से परिपूर्ण होगा। यहाँ कुत्तों के ब्रीड से लेकर उनकी बीमारियों और वैक्सीन आदि पर काम होगा।

नोट :

उत्तर प्रदेश के दो स्टार्ट-अप यूथ को:लैब नेशनल इनोवेशन डायलॉग 2022 में विजेता बने

चर्चा में क्यों ?

27 जून, 2023 को एड-टेक और जैव विविधता में काम करने वाले उत्तर प्रदेश के दो स्टार्ट-अप को यूथ को:लैब नेशनल इनोवेशन डायलॉग इंडिया के 5वें संस्करण में विजेता घोषित किया गया।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि कृषि, एड-टेक, महिलाओं की आजीविका, चक्रीय अर्थव्यवस्था और जैव विविधता में काम करने वाले 9 भारतीय राज्यों के बारह शीर्ष स्टार्ट-अप को यूथ को: लैब नेशनल इनोवेशन डायलॉग इंडिया के 5वें संस्करण में विजेता घोषित किया गया।
- विषयवस्तु 'जैव विविधता संरक्षण पर केंद्रित फिनटेक समाधान विकसित करना'के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के अमन कुमार के स्टार्ट-अप 'नट्टी विलेज - मूंगफली में जैविक मूल्य श्रृंखला बनाने के लिये फार्म का प्रबंधन'को विजेता घोषित किया गया।
- इसी तरह विषयवस्तु 'लाइफ (पर्यावरण के लिये जीवन शैली) के लिये व्यवहारिक सुझाव' के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के संदीप कुमार के स्टार्ट-अप 'डिजी स्वास्थ्य- ग्रामीण भारत के लिये टेलीमेडिसिन'को विजेता घोषित किया गया।
- प्रत्येक विषयगत क्षेत्र के विजेताओं को 5,000 डॉलर का सीड ग्रांट प्राप्त हुआ; जबकि उपविजेता को 3,000 डॉलर प्रा प्राप्त हुए है। यह वित्त पोषण विजेताओं को अपने विचारों को मूर्त उत्पादों या सेवाओं में ढालने में मदद करेगा।
- विदित है कि यूथ को:लैब इंडिया 2022-23 ने 6 विषयगत क्षेत्रों- युवाओं के लिये डिजिटल और वित्तीय साक्षरता, जेंडर समानता और महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण, जैव विविधता संरक्षण पर केंद्रित फिनटेक समाधान विकसित करना, वित्त में प्रौद्योगिकियों के समाधानों के माध्यम से जैव विविधता के अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देना, अपसाइक्लिंग नवोन्मेषणों के माध्यम से चक्रीय अर्थव्यवस्था में तेजी लाना और लाइफ (पर्यावरण के लिये जीवन शैली) के लिये व्यवहारिक सुझाव पर ध्यान केंद्रित किया।
- यूथ को:लैब को 2019 में नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) के साथ साझेदारी में भारत में लॉन्च किया गया था। वर्ष 2022-23 के संस्करण में देश भर के 28 राज्यों से 378 आवेदन प्राप्त हुए।
- आवेदनों में से 47 चयनित स्टार्ट-अप को एसडीजी इनोवेटर्स के लिये एक स्टार्ट-अप सपोर्ट प्लेटफॉर्म यूथ को:लैब स्प्रिंगबोर्ड प्रोग्राम के माध्यम से दो महीने के लिये विशेषज्ञों से प्रत्यक्ष परामर्श और क्षमता-निर्माण सत्र आयोजित किये गए। इन स्टार्ट-अप्स ने इसके बाद मई 2023 में एक प्रतिष्ठित जूरी के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत किये, जिसमें से 12 विजेताओं का चयन किया गया।

नोट :

- अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) के बारे में:
  - स्व-रोज़गार और प्रतिभा उपयोग (सेतु) सहित एआईएम नवोन्मेषण और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार का प्रयास है।
  - इसका उद्देश्य विशेष रूप से प्रौद्योगिकी-संचालित क्षेत्रों में विश्व स्तरीय नवोन्मेषण केंद्रों, बड़ी चुनौतियों, स्टार्ट-अप व्यवसायों और अन्य स्व-रोज़गार गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये एक मंच के रूप में कार्य करना है।
- यूएनडीपी इंडिया के बारे में:
  - यूएनडीपी ने 1951 से भारत में मानव विकास के लगभग सभी क्षेत्रों में काम किया है, जिसमें प्रणाली और संस्थागत मजबूती से लेकर समावेशी विकास और स्थायी आजीविका के साथ-साथ टिकाऊ ऊर्जा, पर्यावरण और लचीलापन शामिल है।
  - यूएनडीपी के कार्यक्रम भारत की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ उत्प्रेरक परिवर्तन के वैश्विक विजन को पूरी तरह से समेकित करते हैं। लगभग हर राज्य में 30 से अधिक परियोजनाओं के साथ, यूएनडीपी इंडिया अलग तरीके से विकास करने के लिये पारंपरिक मॉडलों को रूपांतरित कर सतत् विकास लक्ष्यों को अर्जित करने के लिये काम करता है।
- सिटी फाउंडेशन के बारे में:
  - सिटी फाउंडेशन विश्व में कम आय वाले समुदायों में आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिये काम करता है। यह ऐसे प्रयासों में निवेश करते हैं जो वित्तीय समावेशन को बढ़ाते हैं, युवाओं के लिये रोज़गार के अवसरों को उत्प्रेरित करते हैं और आर्थिक रूप से जीवंत समुदायों के निर्माण के लिये नए दृष्टिकोण की कल्पना करते हैं।
  - सिटी फाउंडेशन का 'परोपकार से भी अधिक' दृष्टिकोण मिशन को पूरा करने और विचार नेतृत्व और नवोन्मेषण को आगे बढ़ाने के लिये सिटी और उसके लोगों की प्रचुर विशेषज्ञता का लाभ उठाता है।
- यूथ को:लैब के बारे में:
  - संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) और सिटी फाउंडेशन द्वारा 2017 में सह-निर्मित, यूथ को:लैब का उद्देश्य एशिया-प्रशांत क्षेत्र के देशों के लिये युवाओं को सशक्त बनाने और उनमें निवेश करने के लिये एक साझा एजेंडा स्थापित करना है ताकि वे नेतृत्व, सामाजिक नवोन्मेषण और उद्यमिता के माध्यम से सतत् विकास लक्ष्य (एसडीजी) के कार्यान्वयन में तेजी ला सकें।

नोट :